>

Title: Alleged delay in the appointment of ad-hoc teachers in Allahabad University and non-filling up of the reservation quota in admission to various courses.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): सभापति महोदय, आज आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में सरकार से बात करना चाहता हूं। यह विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे आज से नहीं से से अधिक वर्ष से पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने भी शिक्षा ली हुई है। मैं भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकला हुआ हूं। इस देश का कोई भी ऐसा सर्वोच्च पद नहीं है जिस पद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हुए लोगों ने सुशोभित न किया हो। भारत की पूरी व्यवस्था में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है चाहे वह राजनीति हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, साहित्य का क्षेत्र हो और चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी पिछले सप्ताह विदेशी शिक्षण संस्थानों को लेकर चर्चा हो रही थी। मानव संसाधन मंत्री जी ने जवाब दिया था कि चूंकि देश में संस्थाएं कम हैं, इसलिए देश के नौजवानों को शिक्षा देने की नीयत से हमें विदेशी शिक्षा संस्थान यहां लाने पड़ रहे हैं। विदेशी संस्थान यहां आए न आए, वे क्या करेंगे, वे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 13 तारीख को जब मैं एक कार्यक्रम में इलाहाबाद में पहुंचा तो जिन गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया है, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला और उसमें से कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। ऐसा शिक्षण कार्य मुझे नहीं करना है। यह स्थिति आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हो गई है। 2005 से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय यू.पी. सरकार के आधीन था और तमाम आंदोलन चले। उन आंदोलनों का परिणाम था कि 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय होने का मौका मिला। लेकिन 2005 के बाद बड़ी उम्मीदें थीं क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष किये थे, आंदोलन किये थे, उन्हें उम्मीद थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा लेकिन मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि आज मुझे अपनी मातृ संस्था की बुराई इस सदन में करनी पड़ रही है।

वर्ष 2005 के बाद वहां हालत यह हो गई कि वहां इलाहाबाद के शिक्षकों की बात करूं तो इलाहाबाद शिक्षक पूरी तरह से परेशान हैं। यू.जी.सी. की जो गोइडलाइन्स हैं, अहार्यता की तिथि से पदनाम, वेतनमान वहां देने की बात को इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्वीकार नहीं कर रहा है। छात्र संघ पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है जिससे प्रशासन के ऊपर कोई लगाम न लग सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आज हालत यह हो गई कि जो भारत सरकार के यूजीसी के पिछड़े वर्ग, दलितों तथा SC/ST के संबंध में जो नार्म्स हैं, 112 से ज्यादा पद खाली हैं, उन पदों को आज नहीं भरा जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जिस विभाग में शिक्षकों की कमी न हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 2005 में छात्रों की संख्या थी, उससे कई गुना संख्या घट गई है। पहले जब मैं वहां पढ़ता था तो छात्रों की लाइन एडमिशन लेने के लिए लगती थी। लेकिन आज अफसोस होता है कि जितनी सीटें हैं, उतनी भी एप्लीकेशंस वहां पर नहीं पहुंच रही हैं। यह दुर्गति वहां हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी और भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि विदेशी संस्थाओं को संरक्षण बाद में दीजिए। पहले हमारा जो "पूर्व का ऑक्सफोर्ड " है, उस ऑक्सफोर्ड को बचा लीजिए और "पूर्व के ऑक्सफोर्ड " की तरह अन्य जो भी विश्वविद्यालय हैं, पहले उनको बचा लीजिए तब इन विदेशी शिक्षा संस्थाओं की पैरवी इस देश के सदन में करिए। यह अपील मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके संरक्षण से भारत सरकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इस देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है, उस संस्थान की गरिमा को बचाएगी।